प्रादेशिक समाचार बुलेटिन,
आकाशवाणी, लखनऊ।

प्रसारण तिथि : 27.07.2026 प्रसारण समय : 19:20 बजे

मुख्य समाचार :–

1. लोकसभा में लोक परीक्षा–अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक, 2026 पेश : परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और सशक्त बनाएगा यह कदम।
2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स के गठन का किया ऐलान।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्म भूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में प्रदेश सरकार को एसआईटी में फोरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का दिया निर्देश : दो हफ्ते में मांगी जांच की पहली स्टेटस रिपोर्ट।

और

4. प्रदेश में रुक–रुक कर बारिश का सिलसिला जारी : मौसम विभाग ने कल अधिकांश ज़िलों में भारी बारिश की दी चेतावनी।

———————————

लोकसभा में आज लोक परीक्षा–अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। बाइट.....

मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा हानी चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट.....

यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाये रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना, और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से, और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर दस साल तक की जेल, दस करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में, विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के, दो महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, तीन महीने के भीतर, मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर, रोक लगाने के साथ–साथ, परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेन्द्र कुमार, आकाशवाणी, समाचार दिल्ली।

———————

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। बाइट.....

लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो। हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नालोजी का उपयोग हो। इन

सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलोजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकेनी जी के नेतृत्व में एक हाई पॉवर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एक्जामेनेशन रिफार्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसकी रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।

इस कार्यबल में इंटेलोजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं।

————————

परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा पर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा एक बार प्रस्तावित कानून बन जाने और टास्क फोर्स के पूरी क्षमता से काम शुरू कर देने के बाद, देश में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। बाइट.....

बिल्कुल बहुत अच्छी कमेटी बनी है। आप सब लोगों ने भी नाम देखा होगा। नंदन जी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बनाया है, श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार ने अपने अपने क्षेत्र के महारथियों को उसमें शामिल किया है और मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण विधेयक जब कानून का शक्ल अख्तियार करेगा और यह टास्क फोर्स अपने जब पूरी तरीके से अस्तित्व में आकर अपने काम को आगे बढ़ाएगा तो पेपर लीक जैसे मामले देश में दोबारा हमको लगता है कि अब सुनाई नहीं देंगे।

————————

सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक

प्रयोग के आरोपों से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस बीच, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है।

———————————

सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल–एसआईटी में एक फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एसआईटी को जांच के संबंध में दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक–आईपीएस अधिकारी एस० किरण की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में एक पुलिस उपमहानिरीक्षक और एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल ने एसआईटी में फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने के पीठ के सुझाव को स्वीकार

कर लिया है। न्यायालय की पीठ मामले के आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच और मंदिर ट्रस्ट के वित्त का लेखा परीक्षा करने की मांग वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी।

उधर इस मामले में अयोध्या में आज एंटी करप्शन कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 10 अगस्त तक बढ़ा दी है।

——————

ब्रेक

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं।

ताज़ा समाचार जानने के लिये आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन ए0आई0आर0 डॉट जी0ओ0वी0 डॉट आई0एन0 पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

——————

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात में देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील की है। इसको लेकर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक

का यह कर्तव्य है कि वह गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। बाइट.....

तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री जी ने लगातार तिरंगा अभियान चलाकर सभी देशवासियों को राष्ट्रभक्ति और उनके कर्तव्यों का बोध कराया है। सुरेश खन्ना के अनुसार, सभी देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से सम्मान और आदर व्यक्त करें और इसे आदर पूर्वक अपने घरों में स्थापित करें।

———————

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 29 जुलाई को वाराणसी से देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलाया जाएगा। वाराणसी में इस आयोजन के बारे मं जानकारी देते हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य ने बताया कि अभियान पांच चरणों में संचालित होगा। इसका उद्देश्य गुरु रविदास के समरसता, कर्मयोग, भक्ति और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन–जन तक पहुंचाना है। बाइट.......

संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में उनके विचारों और आदर्शों को पहुँचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहला कार्यक्रम 29 तारीख को होगा, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूज्य नरेंद्र दास जी के कर–कमलों द्वारा 131 कलशों को पूरे देश में भेजा जाएगा। इन कलशों का विभिन्न जिला मुख्यालयों पर पूजन और सम्मान किया जाएगा।

———————————

राजधानी लखनऊ, श्रावस्ती, अमरोहा और आस–पास के क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और बलिया में घाघरा खतरे के निशान के पास बह रही हैं। वहीं नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ज़िलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

(समाप्त)